

पीएफआरडीए ने नियमों को दी मंजूरी



(एससीबी) को पेंशन कोष शुरू करने की छूट के नियमों को मंजूरी दी है. इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा और ग्राहक सुरक्षा मजबूत करना है. प्रस्तावित नये नियमों के तहत से पीएफआरडीए के समग्र मार्गदर्शन के अंतर्गत समन्वित जागरूकता, पहुंच और वित्तीय-साक्षरता पहल का समर्थन करने के लिए एयूएम का 0.0025 प्रतिशत एनपीएस इंटरमीडियरीज (बिचौलिया फर्मों) के संघ (एएनआई) को दिया जाएगा. पीएफआरडीए के

उभरती वास्तविकताओं, खुदरा और गिग-इकोनॉमी क्षेत्रों में बीमा सुरक्षा का विस्तार करने के उद्देश्य के साथ पीएफआरडीए ने पहली अप्रैल 2026 से पेंशन फंड के लिए निवेश प्रबंधन शुल्क संरचना को संशोधित किया है. संशोधित स्लेब-आधारित आर्गैमएफ में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए अलग-अलग दरें होंगी हैं. एमएसएफ कोष को अलग-अलग गिना जाएगा. कपोजिट स्कीम के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों या स्वतंत्र-चयन और सक्रिय चयन और 100 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का वक्तव्य चुनने वालों के लिए आर्गैमएफ समान रहेगा.

नियामकीय सुधारों में वर्तमान बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है. अभी एनपीएस में बैंकों की भागीदारी सीमित थी. भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुरूप मजबूत बैंकों को ही पेंशन फंड प्रायोजित करने की अनुमति होगी. वित्त मंत्रालय का कहना है कि विस्तृत मानदंड अलग से अधिसूचित किए जाएंगे और नये तथा वर्तमान दोनों पेंशन फंडों पर लागू होंगे. इसके साथ ही एनपीएस

ट्रस्ट के बोर्ड में तीन नये न्यासियों की नियुक्ति की गयी है. इनमें भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, यूटीआई एमएसी - ट्रस्ट की पूर्व कार्यकारी उपाध्यक्ष स्वाति अनिल कुलकर्णी, डिजिटल इंडिया फाउंडेशन के सह-संस्थापक और प्रमुख और सिडबी द्वारा प्रबंधित फंड ऑफ फंड्स स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यम पूंजी निवेश समिति के सदस्य डॉ. अरविंद गुप्ता शामिल हैं.

विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि 38 महीने के निचले स्तर पर



मुंबई, 02 जनवरी. नये आँडों में सुस्ती से विनिर्माण क्षेत्र की उत्पादन वृद्धि दर माह-दर-माह आधार पर दिसंबर में घटकर 38 महीने के निचले स्तर पर आ गयी.

एसएंडपी ग्लोबल द्वारा शुरूवार को जारी एचएसबीसी भारतीय विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक रिपोर्ट में यह बात कही गयी है. भारतीय विनिर्माण क्षेत्र का पीएमआई दिसंबर में घटकर 55 रह गया. यह दो साल से ज्यादा समय में विनिर्माण क्षेत्र की

गतिविधियों में सबसे सुस्त वृद्धि को दर्शाता है. नवंबर में पीएमआई 56.6 रहा था. पीएमआई का 50 से ऊपर रहना गतिविधियों में वृद्धि को और इससे कम रहना गिरावट को दर्शाता है. इसका 50 का स्तर स्थिरता का द्योतक है. एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेल्जेंस में इकोनॉमिक्स एसोसिएट डायरेक्टर पॉलियाना डी लीमा ने रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, वृद्धि की रफ्तार कम पड़ने के बावजूद भारतीय विनिर्माण उद्योग का प्रदर्शन 2025 में अच्छा रहा. हम वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में प्रवेश कर रहे हैं और ऐसे में नये कारोबार में तेज वृद्धि के कारण कंपनियों के व्यस्त रहने की उम्मीद है.

वस्त्र मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आठ-नौ जनवरी को गुवाहाटी में

नई दिल्ली, 02 जनवरी. राज्यों के वस्त्र मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आठ से नौ जनवरी तक असम के गुवाहाटी में आयोजित किया जायेगा. यह जानकारी केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने गुरुवार को दी. मंत्रालय ने कहा है कि दो दिन के इस सम्मेलन में देशभर के राज्यों के वस्त्र विभाग के मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. इस सम्मेलन का उद्देश्य नीतिगत समन्वय, क्षेत्रीय विकास तथा भारत के वस्त्र क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों पर चर्चा करना है. इस सम्मेलन के साथ ही वहां पूर्वोत्तर सम्मेलन (नॉर्थईस्ट कॉन्क्लेव) का आयोजन किया जाएगा, जिसका मुख्य फोकस पूर्वोत्तर क्षेत्र के वस्त्र क्षेत्र को सशक्त और मजबूत बनाना होगा.

सोने-चांदी के दामों में आई तेजी

1.34 लाख पार पहुंचा सोना
2.34 लाख तक पहुंची चांदी



नई दिल्ली, 02 जनवरी. सोने और चांदी के दामों में आज अचानक तेजी देखी गई है. 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 954 रुपए बढ़कर 1,34,415 और 1 किलो चांदी 5,656 बढ़कर 2,34,906 पर पहुंच गई.

तीन दिन की गिरावट के बाद यह तेजी निवेशकों के लिए राहत लेकर आई है. डॉलर की कमजोरी, रूस-यूक्रेन संघर्ष और वैश्विक मांग तेजी के प्रमुख कारण रहे. विशेषज्ञों का कहना है कि इस

दिसंबर 2025 में सोने का ऑल टाइम हाई

1.38,161 और चांदी 2,43,483 प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया था. सोने में तेजी के पीछे डॉलर कमजोर होना, वैश्विक जियोपॉलिटिकल तनाव और चीन जैसे देशों की लगातार खरीदारी मुख्य कारण हैं. वहीं चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड, अमेरिकी टैरिफ के डर और मेन्यूफैक्चर्स की होड ने दाम बढ़ाए हैं. कैडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय कैडिया के अनुसार, चांदी की मांग में तेजी आगे भी बनी रहेगी और यह 2.75 लाख तक जा सकती है. सोने का भाव भी साल के अंत तक 7.50 लाख प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच सकता है. सोना खरीदते समय हमेशा हॉलमार्क वाला सर्टिफाइड गोल्ड और सही कीमत का क्रॉस-चेक करना जरूरी है.

शेयर बाजारों में तेजी, सेंसेक्स 573 अंक उछला

मुंबई, 02 जनवरी. विदेशों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को तेजी रही और बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सूचकांक सेंसेक्स 573.41 अंक (0.67 प्रतिशत) की बढ़त में 85,762.01 अंक पर बंद हुआ. बाजार में आज शुरु से ही तेजी रही.



चौतरफा लिवाली के बीच 01 फरवरी से पान मसाला, सिपेट-बोड़ी तथा अन्य तंबाकू उत्पादों पर उपकर और कर बढ़ाने की अधिसूचना के बाद एफएमसीजी कंपनी आईटीसी के शेयरों में लगातार दूसरे दिन गिरावट रही. इसका शेयर आज जीने चार

प्रतिशत टूट गया. मझौली और छोटी कंपनियों के सूचकांक भी बढ़त में रहे. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.94 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.72 प्रतिशत चढ़ा. एफएमसीजी को छोड़कर अन्य सभी सेक्टरों में तेजी रही. रियल्टी, धातु, ऑटो, वित्त, बैंकिंग और टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद समूहों की कंपनियों में लिवाली ज्यादा रही. एनटीपीसी का शेयर चार प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा. टैट में ढाई फीसदी से अधिक की तेजी रही. बजाज फाइनेंस,

चावल, चीनी, दालों में तेजी गेहूं, खाद्य तेलों के भाव टूटे

नई दिल्ली, 02 जनवरी. घरेलू थोक जिन बाजारों में शुक्रवार को चावल के औसत भाव बढ़ गये. चावल के साथ चीनी और दालों में भी तेजी रही जबकि गेहूं और खाद्य तेलों में गिरावट का रुख रहा. औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत पांच रुपये बढ़कर 3,823 रुपये प्रति क्विंटल हो गयी. गेहूं तीन रुपये प्रति क्विंटल सस्ता हुआ और 2,853 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बोला गया. आटा छह रुपये महंगा हुआ. दाल-दलहनों में तेजी रही. तुअर दाल

मार्च के अंत से तीन साल में एक बार होगा निदेशकों का केवाईसी

नई दिल्ली, 01 जनवरी. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनियों के निदेशकों को एक बड़ी राहत देते हुए वार्षिक केवाईसी (पहचानों अपने ग्राहकों को) की जगह तीन वर्ष में एक बार संक्षिप्त केवाईसी की व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है. मंत्रालय की गुरुवार को जारी एक के अनुसार नयी व्यवस्था 31 मार्च 2026 से लागू होगी. इस मामले में परामर्श और चर्चा का यह निर्णय गैर-वित्तीय विनियामक सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है. कंपनियों (निदेशकों) की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 के नियम 12क में किये गये संशोधन को बुधवार 31 दिसंबर 2025 को अधिसूचित किया गया. संशोधित सरल केवाईसी फॉर्म का उपयोग केवाईसी की शर्तों के अनुपालन के साथ-साथ निदेशकों के मोबाइल नंबर, ईमेल पता, आवासीय पता अपडेट करने और निदेशक पहचान संख्या (डिन) को पुनः सक्रिय करने के लिए किया जा सकेगा.

निर्यातकों के लिए सरकार की बड़ी मदद



करीबी 3,100 करोड़ मंजूर, 8,599 करोड़ आवेदन आए पहले ही महीने सेकड़ों एमएसएमई इकाइयों को राहत

नई दिल्ली, 02 जनवरी. केंद्र सरकार ने निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से लागू करने के बाद पहले महीने में 8,500 करोड़ रुपये से अधिक के आवेदन और 3,100 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृतियां प्रदान की हैं.

सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम क्षेत्र के निर्यातकों को नकदी बाजार विविधीकरण और रोजगार संवर्धन में मदद देने के लिए यह योजना पहली दिसंबर 2025 से लागू की गयी है. इस योजना के तहत सरकार उन्हें अतिरिक्त ऋण सुविधा पर 100 प्रतिशत गारंटी की सुविधा प्रदान

कर रही है. वित्तीय सेवा विभाग द्वारा क्रियान्वित सीजीएसई के तहत बैंक और वित्तीय संस्थान इस समय अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों के दौरान भारतीय निर्यातकों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है. यह योजना पात्र प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष निर्यातक एमएसएमई इकाइयों को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त, बिना जमानत कर्ज सहायता प्रदान करने के लिए है. वित्त मंत्रालय के अनुसार पहले महीने 31 दिसंबर तक कुल राशि 8,599 करोड़ रुपये की राशि के कर्ज के लिए 1,788 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से 716 आवेदनों को 3,141 करोड़ रुपये की राशि के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है. योजना के तहत निर्यातकों को उनके मौजूदा निर्यात ऋण/कार्यशील पूंजी सीमा के 20 प्रतिशत तक के बराबर कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. योजना 31 मार्च तक या 20,000 करोड़ रुपये तक की गारंटी जारी होने तक (जो भी पहले हो) खुली रहेगी.

एन सी एन NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (मिनिरल कंपनी) (कोल इण्डिया लिमिटेड की एक अनुपुगी कम्पनी)

निविदा सूचना

सीआईएल एवं अनुपुगी कम्पनियों द्वारा सामग्री, कार्य एवं सेवाओं हेतु निर्गत सभी निविदाएँ www.coalindia.in/ सम्बंधित अनुपुगी कम्पनी, सीआईएल ई-प्रक्रियारमेट पोर्टल <https://coalindiatenders.nic.in> एवं केंद्रीय लोक प्रक्रियारमेट पोर्टल <https://eprocure.gov.in> पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त GeM Portal <https://gem.gov.in> के द्वारा भी प्रक्रियारमेट किया जाता है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय : भोपाल

वित्तीय आरक्षकों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस

वित्तीय आरक्षकों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत निम्नानुसार उधारकर्ता/गारंटर को निम्नानुसार उनके अंतिम ज्ञात पते पर देय ऋण एवं ब्याज का भुगतान 60 दिनों के अंदर करने को नोटिस प्रेषित की गई थी। परंतु उक्त नोटिस संबंधित व्यक्ति पते पर न पाये जाने के कारण वापिस आ चुकी है।

उधारकर्ता/गारंटर का नाम तथा बैंक शाखा का नाम

बैंक संघर्ष के अन्तर्गत संपत्ति/प्रतिभूति का विवरण एवं संपत्ति मालिक का नाम

धारा 13(2) के अन्तर्गत जारी नोटिस दिनांक एवं देय दिनांक

मुण्डीयावा हाट शाखा, भोपाल

संघर्ष संपत्ति विहायशी फ्लैट क्षेत्रफल- 43.67 वर्गमीटर स्थित फ्लैट नंबर 204, द्वितीय तल, वाई कॉलोनी - एमपी नगर जेल - 2 मुख्य मार्ग से हटकर, जिला-भोपाल, जिला उप क्षेत्र 141, एसबीआई कॉलोनी रोड, जेल 2, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश, बांदा पावर टूथस पिन -262023 (भारत) से 4 मीटर दूर, संपत्ति मालिक- मुण्डीयावा मेहरा पुरी केएस मेहरा, एजीकृत सेल डीड नं. MP43IGR169522024S100066634 दिनांक 17.12.2024 उप/संयुक्त रजिस्ट्रार भोपाल में पंजीकृत (संपत्ति का विवरण किलेख के अनुसार होना चाहिए) धर्तरीसामान- पूर्व: फ्लैट नंबर 202, पहिलम: फ्लैट नंबर 140, उत्तर: खुला, पहिलम: फ्लैट नंबर 203

35,10,995.99 ₹

पुनर्गठन दिनांक 19.07.2025

उपरोक्त संबंधित उधारकर्ता/गारंटर एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि को एवढ द्वारा सूचित किया जाता है कि 60 दिनों के पूर्व उपरोक्त संगुण राशि ब्याज एवं खर्चों सहित भुगतान करने अथवा सरफेसी अधिनियम के तहत उपरोक्त संपत्ति के कब्जा एवं विक्री की कार्यवाही अधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी। स्थान: भोपाल प्राधिकृत अधिकारी दिनांक - 03.01.2026

कार्यालय नगर पालिक निगम, खण्डवा

पता- आजाद भवन टाउन हिल खण्डवा, 450001 दूधभंग-0733 2223523

ईमेल- commkhandwa@mpurban.gov.in

क्रमांक/क्र. रा. बा. / 2025/961

खण्डवा, दिनांक 31/12/2025

// अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण सूचना विज्ञापन //

निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा ऑनलाइन आमंत्रित की जाती है, उल्लेखित कार्य की निविदा का विस्तृत वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	ऑनलाइन पोर्टल	कार्य का नाम	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र की राशि	कार्य की अवधि
1	2025_UAD_472224_1	मा नवचण्डी मेला हेतु आरक्षित भूमि को मेला अवधि (2 माह के लिये) में अस्थाई आवंटन हेतु	21,26,000/-	1,00,000/-	5,000/-	अनुबंध दिनांक से 02 माह तक

निविदा ऑनलाइन क्रय तथा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :- 13/01/2026 (शाम 05:30 बजे तक)

निविदा खोलने की दिनांक :- 15/01/2026 (शाम: 10:30 बजे)

निविदा संबंधी समस्त जानकारी वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदा में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो वह समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जावेगा। ई निविदा से संबंधित शर्तें कार्यालयीन समय में राजस्व बाजार विभाग में देखी जा सकती है।

आयुक्त नगर पालिक निगम खण्डवा

योगी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की तैयारी

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है. मुख्यमंत्री आवास पर हुई कोर कमिटी की मैराथन बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी दिल्ली रवाना हो गए हैं. माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद सरकार और संगठन में 'अदला-बदली' के फॉर्मूले पर अमल किया जाएगा.



मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर करीब डेढ़ घंटे तक चली कोर कमिटी बैठक में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर गहन मंथन हुआ. इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री और आरएसएस के पदाधिकारियों की मौजूदगी में यह संकेत दिए गए कि संगठन के कुछ पुराने चेहरों को सरकार में लाया जा सकता है, जबकि वर्तमान मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. सूत्रों के

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल

भोपाल के विभिन्न स्थानों पर भवन/भूखण्ड/ऑफिस हॉल एवं रायसेन में ई.डब्ल्यू.एस. भवन यथास्थिति में ऑफर के माध्यम से विक्रय हेतु उपलब्ध

ई-ऑफर दिनांक 29.01.2026 (राशि 23:59 बजे तक)

क्र.	योजना का नाम	उपलब्ध भवन क्रमांक	भवन का निर्मित क्षेत्रफल (व.मी.)	युक्तियुक्तकरण में अपसेट मूल्य (रु. लाख)	धरोहर राशि (रु. लाख)	आवेदन शुल्क (रु./ए.एस.टी. सहित)
द्वारिका परिसर अरविन्द विहार, बागमुगालिया, भोपाल में फ्लैट						
1.	HIG 2 BHK (4th Floor)	516, 517	92.68	32.12	6.43	2360/-
2.	HIG 2 BHK (5th Floor)	615, 616, 618, 619, 620 (कुल 05)	92.68	32.12	6.43	2360/-
3.	Office Hall (Block-E)	2, 4, 8, 10, 12 (कुल 05)	186.00	157.72	23.66	4720/-
4.	Office Hall (Block-E)	3, 7, 9, 11 (कुल 04)	195.00	157.72	23.66	4720/-
5.	पूर्वांचल परिसर बागमुगालिया के फ्लैट 3 BHK	301, 302, 304, 402, 403 (कुल 05)	110.50	35.31	7.06	2360/-
6.	304 एल.आई.जी. प्रकोष्ठ एकतापुरी	जूनि. एल.आई.जी. 5/119	27.10	3.81	0.76	590/-
7.	कृषि उपज मंडी के पास रायसेन में ई.डब्ल्यू.एस. आवासीय भवन	23, 28, 35 से 39, 66 से 74, 76 से 80, 87 से 89 एवं 91 से 93, 83, 84, 86, 94 से 97, 100, 101, 21, 40, 65, 82 एवं 101-ए	20.28	4.19 से 4.44 तक	0.84 से 0.89 तक	590/-
8.	“आम्रपाली आकेड व्यावसायिक परिसर” बागमुगालिया एक्सटेंशन भोपाल में ऑफिस चेम्बर	ए-9 एवं ए-10, ए-12, ए-2 एवं ए-11, ए-5 एवं ए-8, ए-6 एवं ए-7, सी-1, सी-2, सी-4, सी-5, सी-6, सी-8	16.94 से 37.62	9.96 से 22.15 तक	1.99 से 4.43 लाख तक	1770/-
व्यावसायिक/शाला/भूखण्ड अयोध्या नगर, भोपाल						
1.	भूखण्ड एम.सेक्टर (सस्वती स्कूल के पास)	भूखण्ड का क्षेत्रफल- 2352.00 व.मी.	रु. 916.67 लाख	रु. 137.50 लाख	5900/-	
2.	भूखण्ड के.सेक्टर (एच.आई.जी. 20 के पास)	भूखण्ड का क्षेत्रफल-1848.00 व.मी.	रु. 721.06 लाख	रु. 108.16 लाख	5900/-	
3.	शाला भूखण्ड जी.सेक्टर	भूखण्ड का क्षेत्रफल-4298.70 व.मी.	रु. 247.07 लाख	रु. 37.06 लाख	2360/-	
आवासीय भूखण्ड अयोध्या नगर, भोपाल						
क्र.	योजना का नाम	उपलब्ध भूखण्ड क्रमांक	उपलब्ध भूखण्ड का क्षेत्रफल (व.मी.)	अपसेट मूल्य (रु. लाख)	धरोहर राशि (रु. लाख)	आवेदन शुल्क (जी.एस.टी. सहित)
1.	आवासीय भूखण्ड एच.आई.जी. ई-सेक्टर	48 एवं 49 (02)	213.60	रु. 65.13 लाख	रु. 9.77 लाख	2360/-

नोट :- (1) ऑफर स्वीकृत होने पर रुपये 50.00 लाख या उससे अधिक की अपसेट मूल्य की संपत्ति की शेष राशि 3 आसान किस्तों में भुगतान करने की विशेष सुविधा। (2) संपत्ति के ऑफर स्वीकृति उपरांत ऑफरकर्ता द्वारा ऑफर निरस्त कराने पर मण्डल नियमानुसार धरोहर राशि की 50 प्रतिशत राशि बचत कर ली जावेगी। (3) ऑफर प्रस्तुत करने के पूर्व स्थल/संपत्ति का अवलोकन कर लें। (4) शासन/मण्डल द्वारा निर्धारित लीजरेट एवं प्रकोष्ठ भवनों के मूल्य का 5% कार्पस फंड एवं अन्य कर/शुल्क पृथक से देय होंगे। (5) आवेदन शुल्क एवं धरोहर राशि Online/RTGS से जमा होगी। रजिस्टर्ड मोबाइल पर BID-ID प्राप्त होगी। (6) आवेदन धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि 29.01.2026. (7) ऑफर डालने की अंतिम तिथि 30.01.2026 सायं 5:00 तक। (8) ऑफर बिनाक 02.02.2026 को सायं 3.00 बजे खोले जायेंगे। (9) आवेदन फार्म का मूल्य एवं धरोहर राशि Online/RTGS से जमा होगी। (10) रजिस्टर्ड मोबाइल पर BID-ID प्राप्त होगी। (11) मण्डल/शासन के नियम/शर्तें लागू। (12) योजना की विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.mphousing.in पर उपलब्ध।

संपर्क :- एम.पी. खरे (सहायक यंत्री) मो. 9827290842 (अयोध्या हेतु), संतोष चतुर्वेदी (उपयंत्री) मो. 94606912066 (बागमुगालिया हेतु), श्रीमती स्नेहा सोनी (संपदा प्रबंधक) मो. 9713055625, श्रीमती राजकुमारी मालव्या (संपदा प्रबंधक) मो. 9826853657

M.P. Online Help Line 0755-6720200 (राजेश शुक्ला)

म.प्र. माध्यम/12381/2026 संपदा अधिकारी, प्रक्षेत्र-2, भोपाल (मो. 9425012768)

ऑनलाइन भुगतान में सुविधा होने पर Whatsapp Helpdesk Number 7974264023

पंजीकृत आवंटनी अब अपनी समस्त देय राशि का भुगतान मंडल के मोबाइल एप (MPHIDB GEO जो Google Play Store पर उपलब्ध है) के माध्यम से भी कर सकते हैं। दिये गये QR-Code को स्कैन कर भी एप डाउनलोड कर सकते हैं।

Follow us on [Facebook](https://www.facebook.com/mphidb) /mphidb